

::प्रधानआयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::  
O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



**रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-**

क	अपील / फाइल नं./ Appeal / File No.	मूल आदेश नं./ O.I.O. No.	दिनांक/ Date
	V2/42 /GDM/2018-19	08/2018-19/11	24.05.2018

ख अपील आदेश नं./ (Order-In-Appeal No.):

**KCH-EXCUS-000-APP-062-2019**

आदेश का दिनांक / Date of Order:	11.06.2019	जारी करने की तारीख / Date of issue:	13.06.2019
------------------------------------	------------	--	------------

श्री कुमार संतोष, प्रधान आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /  
Passed by Shri Kumar Santosh, Principal Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अग्र आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ मेवाकर/ वस्तु एवं सेवा कर,  
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से नृजित: /  
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,  
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

**M/s Adani Wilmar Limited, Village-Dhrub, Mundra, Kutch-370421, .**

इस आदेश (अपील) में न्यायित कहे व्यक्ति निम्नलिखित तरिके में उपयुक्त प्राधिकार / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/  
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) माना शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेवाकर अधीन न्यायाधिकरण के अंतर्गत अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 का धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/  
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण सुझावों से संबंधित सभी मामलों में माना शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, का की जानी चाहिए।/  
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में ब्रतानग अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें मीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, द्वितीय तल, बहुमाली भवन अनावा अहमदाबाद- 380016 का की जानी चाहिए।/  
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumai Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 का चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के महायुक्त रजिस्ट्रार के नाम में किसी भी नार्बजित क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/  
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty/demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत मेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उक्त साथ जिन आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होना चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां मेवाकर की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के महायुक्त रजिस्ट्रार के नाम में किसी भी नार्बजित क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/  
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



(i) बिना अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रारूप S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उनका साथ आवृत्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अध्यायक आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उत्तम में एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण का आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति की साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 of the Finance Act 1994, shall be filed in Form S.T.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टाट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धारा 35एक के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, उन आदेशों के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%)। जब मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इन धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दम कंगेड नया से अधिक न हो।

- (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किया गया शुल्क" में निम्न शामिल है
- (ii) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- (iii) मन्वेट जमा की गयी गई गलत राशि
- (iv) मन्वेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते वह कि इन धारा के प्रावधान विनियम (नं. 2) अधिनियम 2014 के अंतर्गत में पूर्व किमी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचारणीय न्यूनतम अर्जी एवं अपील की लागू नहीं होगी। / For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

- Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
- (i) amount determined under Section 11 D;
  - (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
  - (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन : **Revision application to Government of India:** इन आदेशों की पुनरीक्षण या निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम उपबन्ध के अंतर्गत अवर सूचिद, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, बिना संशोधन, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जवाब दीप भवन, संसद भवन, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (i) of Section-35B ibid:

(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी गन्तु या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कड़े माल पर भंगी नई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (निवेत) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी गन्तु या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) मुनिष्ठित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो छूटी क्रेडिट इन अधिनियम एवं इनके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा बिना अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई लागू अथवा समायोजित पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियाँ प्रारूप संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इन आदेश के संप्रयोग के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के माध्यम के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule. 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए : जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000/- का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इन आदेशों में कोई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग में किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होने हुए भी की लिखा पत्र कार्य में बचत के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाना है। / In case, if the order covers various numbers of order-in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) यथास्थिति न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थान आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा जाना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमवली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और त्वरिततम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in).



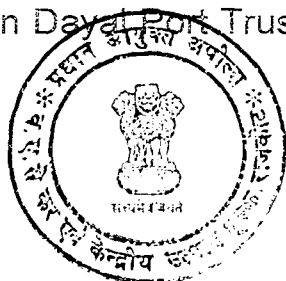
:: ORDER IN APPEAL ::

M/s. Adani Wilmar Ltd., Village – Dhruh, Mundra, Kutch – 370421 (hereinafter referred to as 'appellant') filed present appeal against Order-in-Original No. 8/2018-19 dated 24.5.2018 (hereinafter referred to as "impugned order") passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division, Mundra (Kutch) (hereinafter referred to as "the adjudicating authority"): -

2. The brief facts of the case are that the appellant filed refund claim of Rs. 44,45,587/- under Notification No. 41/2012-ST dated 29.6.2012 in respect of service tax paid on services received and used for export of goods. The lower adjudicating vide impugned order sanctioned refund claim for Rs. 43,71,614/- and rejected refund claim of Rs. 73,973/-.

3. Being aggrieved with the impugned order, appellant preferred the present appeal, *inter-alia*, on the following grounds: -

(i) Deen Dayal Port Trust has raised 12 bills dated 15.6.2017 on the appellant for wharfage charges under which service tax of Rs. 73,973/- has been charged. The appellant engaged M/s. J.R. Roadlines Pvt. Ltd. as a pure agent to make the payment to Deen Dayal Port Trust on behalf of the appellant, who in turn instructed its sister concern M/s. Nidhi Shipping Pvt. Ltd. Accordingly, M/s. Nidhi Shipping Pvt. Ltd. made payment of Rs. 5,67,123/- including service tax of Rs. 73,973/- which issued Receipt Vouchers evidencing receipt of payment. M/s. J.R. Roadlines Pvt. Ltd. has reimbursed the payment incurred by M/s. Nidhi Shipping Pvt. Ltd. and raised Debit Notes on the appellant for recovery of Rs. 5,67,123/-. M/s. J.R. Roadlines Pvt. Ltd. had issued certificate to this effect and also certified that they had not availed cenvat credit on service tax paid. Therefore, it is evident that the incidence of service of Rs. 73,973/- has been borne by the appellant. The appellant has submitted copy of debit notes raised by M/s. J.R. Roadlines Pvt. Ltd. along with all relevant documents, copy of payment receipt vouchers issued by Deen Dayal Port Trust, copy of certificate issued by M/s. J.R.



*[Handwritten signature]*

Roadlines Pvt. Ltd. and copy of letter issued by M/s. J.R. Roadlines Pvt. Ltd. certifying that they have reimbursed the amount to M/s. Nidhi Shipping Pvt. Ltd. in respect of payment made to Deen Dayal Port Trust on behalf of the appellant and have recovered the same from the appellant by issuing debit notes. The lower adjudicating authority has erroneously overlooked 12 bills issued by Deen Dayal Port Trust issued in favour of the appellant and treated the Receipt voucher as bills. The Receipt voucher also gives a reference to Bill voucher number issued by Deen Dayal Port Trust.

(ii) It is nowhere laid down under the law that for a unit to be treated as sister concern, the unit ought to have same service tax and Income Tax PAN. A sister company is a company with close affiliations to another company with separate name and personnel. Both companies are owned by the same parent and are considered subsidiaries of the larger company. One parent company can have one or many subsidiaries, which all are sister companies to each other. They belong to same promoter or some founder.

(iii) The appellant has complied with the conditions laid down under Notification No. 41/2012-ST dated 29.6.2012 and therefore, refund of service tax cannot be denied on the ground that the invoices issued by the service provider indicate the name of M/s. Nidhi Shipping rather than J.R. Roadlines to whom the payment is said to have been made by the appellant. The only condition laid down under Notification No. 41/2012-ST dated 29.6.2012 is that invoice should evidence payment for the specified service used for export of goods and payment of service tax on the said service. The invoices issued by Deen Dayal Port Trust contained name of the appellant and shipping bill numbers and payment vouchers indicated the payment of service tax to the service provider and therefore, refund of service tax cannot be denied.

(iv) It is settled principle of law that substantive benefit cannot be denied on procedural grounds and therefore once, there was no dispute that the subject goods have been exported and the specified services have been used for export of goods and payment of service tax has



been made by the appellant, the refund cannot be denied on the round that the invoices issued by the service provider carries the name of M/s. Nidhi Shipping Pvt. Ltd. and not M/s. J.R. Roadlines especially when the name of the appellant and the shipping bill numbers are reflected in the invoices issued by the service provider. The appellant relied on decisions in the case of Ford India Ltd. reported as 2011 (272) ELT 353 (Mad.) and Madhav Steel reported as 2016 (337) ELT 518 (Bom.).

4. Personal hearing in the matter was attended by Shri S.J. Vyas, Advocate, who reiterated the grounds of appeal.

**FINDINGS:**

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the grounds of appeal and the submissions made during personal hearing. I find that this being the case of refund, provisions of Section 35F(i) of the Central Excise Act, 1944 are not applicable. The issue to be decided in the present case is as to whether rejection of refund claim filed under Notification No. 41/2012-ST dated 29.6.2012 is correct or not.

6. The lower adjudicating authority has rejected refund claim of service tax of Rs. 73,973/- paid on wharfage charges to Deen Dayal Port Trust on the ground that invoices issued by the said port authority were in the name of M/s. Nidhi Shipping and not M/s. J.R. Roadlines and that both these units have separate service tax and income tax PAN and hence, no relation between these two units can be established. I find that the inference drawn by the lower adjudicating authority is not correct, legal and proper for the reason that invoices issued by the port authority for wharfage charges and service tax due thereon contained details of shipping bill No., vessel name, description of goods, name of the exporter etc. from which co-relation of payment of service tax on wharfage charges with use of said service for export of goods is established. I further find that the certificate issued by M/s. J.R. Roadlines clearly states that they paid wharfage to M/s. Nidhi Shipping Pvt. Ltd. and that they raised debit note to appellant. I further find that



appellant has submitted copy of debit notes issued by M/s. J.R. Roadlines on the appellant and copy of ledger of the appellant indicating payment of service tax made to M/s. J.R. Roadlines. From the above documents, it is evident that the appellant suffered incidence of service tax paid on wharfrage charges and use of service for export of goods and export of goods are not disputed and hence, I hold that rejection of refund under the impugned order is not correct, legal and proper.

7. In view of above, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the appellant.

7. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

8. The appeal filed by the appellant is disposed off in above terms.

*[Handwritten Signature]*  
13/11/19

(कुमार संतोष)  
प्रधान आयुक्त (अपील्स)

**By Speed Post**

To,

M/s. Adani Wilmar Ltd.,  
Village - Dhruv,  
Mundra, Kutch - 370421

मेसर्स अदानी विलमर लिमिटेड,  
गाँव - ध्रुव,  
मुँदरा कच्छ - ३७०४२१

प्रति:

- (1) प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर, अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- (2) आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (3) सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर मण्डल, मुँदरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(4) गार्ड फ़ाइल